श्री अजीत जोगी : इस पर चर्चा हो जाय ।

उपसभापति : नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, चर्चा करेंगे डिसकशन करेंगे प्लान के ऊपर, मगर इस सवाल पर इतना नहीं होगा ।

हथकरघा उद्योग की स्थापित क्षमता

*466. **श्री बीरेन जे० शाह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में स्थापित हथकरघा उद्योग की क्षमता का कोई अनुमान लगाया गया है ; यदि हां तो इस क्षेत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि हथकरघा क्षेत्र अपनी पूरी उत्पादन क्षमतानुसार कपड़े का उत्पादन नहीं कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन न होने का कारण पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल का उपलब्ध नहीं हो पाना है ; और

(घ) हथकरघा क्षेत्र को प्रति वर्ष उसकी आवश्यकता से कितनी कम मात्रा में सूत उपलब्ध कराया जाता है और क्या सरकार सूत-आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दत्तात्रेय गहलोत) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां । उत्पादकता और मांग में विभिन्नता तथा हथकरघा क्षेत्र में विकेंद्रीकृत उत्पादन को मद्देनजर रखते हुए अंतरिम तौर से यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 4000 मिलियन मीटर से भी अधिक है ।

(ख) कपड़े का उत्पादन भी इसकी क्षमता के लगभग ही है लेकिन उत्पादन मांग पर निर्भर करता है और इस लिए घटता-बढ़ता रहता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) हथकरघा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 450 मिलियन किलोग्राम से भी अधिक हैंक यार्न उत्पादन में विभिन्नता के आधार पर उपलब्ध होता है तथा उत्पादन कपड़े की मांग पर निर्भर करता है ।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Madam, it is evident from the reply of the hon. Minister that the handloom sector stands on a very low priority because according to the statement, the Minister says that there is no shortage of the hank yarn and that the production is governed by the supply and the demand. Thus the Minister knows that there is an increase in the prices. I would like to give the figures; the hank yarn used to be sold at Rs. 63.8 per kg and and now the current price is Rs. 79.29 per kg. And this increase in price has been there because of the shortage of the hank yarn. So there is no dispute about the the fact that there is a shortage of the hank yarn in the country. But the purpose of my asking this question was to seek the help of the hon. Minister to avoid shortages which affect the interests of a number of handloom weavers. Madam, my point is that the shortage is on account of non-functioning and non-performig of the statutory obligation by the State-run National Textiles Corporation. There is a statutory obligation that they should have 50 per cent of their marketable output...

उपसभापति : आप बहुत संक्षेप में सवाल करें तो मेहरबानी होगी ।

*सभा में यह प्रश्न डा० जिनेन्द्र कुमार जैन द्वारा पूछा गया ।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: As the answer was not correct, I had to explain. Now my question is, there is a statutory obligation of producing hank yarn to the extent of 50 per cent of the marketable output. At the moment, it is only 17 per cent. What does the Government propose to do to increase this production by the mills controlled by the National Textiles Corporation and thus meet the shortages?

श्री अशोक गहलोत : मैडम, जैसा मैंने कहा कि हैंक यार्न की शोर्टेज नहीं है बल्कि हैंक यार्न की प्राइसेज काफी बढ़ गई है, इस बात को स्वीकार किया गया है। इसके कारण हैन्डलूम वीवर्स को ज्यादा समस्या हो रही है। मेरे पास आंकड़े हैं। उनसे साफ जाहिर है कि हैंक यार्न जितना करीब करीब चाहिए उतना हैंक यार्न मिल रहा है। परंतु प्राइसेज बढ़ने के कारण जो तकलीफ आ रही है। उसके कारण हम लोगों ने पहले भी कोशिश करी कि उस प्राइसेज को स्टेबिलाइज करें और आपको यह जानकर खुशी होगी कि मार्च से प्राइसेज स्टेबिलाइज हो गई है। जहां तक हैंक यार्न प्रोडक्शन की बात कही गई है, हैंक यार्न आब्लिगेशन स्कीम के अंतर्गत एन.टी.सी. के बारे में आपने कहा, बिल्कुल मैं उसको स्वीकार करता हूं क्योंकि एन.टी.सी मिलों की जो हालत बनी हुई है उससे जो प्रोडक्शन है वह कई कई मिलों में 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत तक आ गया है और इसलिए वे आब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कोशिश है और एन.टी.सी. का जो रिस्ट्रक्चरिंग करने का जो प्लान है उसके पूरा होते ही हम खुद चाहेंगे कि जिस प्रकार से यह दूसरी मिलों पर लागू होता है हैंक यार्न आब्लिगेशन एक्ट, उसी ढंग से एन.टी.सी. भी इसको स्वीकार करे।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Madam, is it not a fact that cotton is a raw material that we export? Is it not a fact that the requirement of cotton to produce sufficient amount of hank yarn is only round 12 per cent of the cotton that we produce? I would like to know from the hc Minister whether his Ministry is goir to import two lakh bales of cottc for the production of hank yarn f the handloom sector? On the o hand, we are not making hank ya of our own cotton... (*Interruption*

उपसभापति : अभी आप एक्सप्लेनेश न दें। सवाल पूछ लीजिये Let him answer what is he doing.

श्री अशोक गहलोत : महोदया, पिछले सेशन में भी, आपको मालूम होगा कि हैंक-यार्न की प्राबलम को लेकर काफी सवालात यहां पर हुए थी। उस वक्त ऐसी स्थिति बनी थी और गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी कि दो लाख क.टन बेल डयूटी फ्री इम्पोर्ट करें, किसी तरह उसको कन्वर्ट करवायें और वह हैंक-यार्न हैंडलूम वीवर्स को मिल सके। परन्तु वह स्कीम चल नहीं पायी और जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहां पर काटन उपलब्ध रहा और वहां पर उसकी प्राइस ज्यादा बढ़ गयी। इसके कारण यह स्कीम चल नहीं पायी।

THE DEPUTY CHAIRMAN: M Prakada Kotaiah... (*Interruption*) .. Your question is already over.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Madam, my point is that handloon weavers are the poorer sections o the society . . . (*Interruptions*) .. Won't you allow me... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have allowed two supplementaries Now let Mr. Kotaiah, who is the torch bearer for the problems of the handloom weavers, ask a question.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Madam, no full answer was given by the Minister. He did not indicate the number of handlooms working in this country. There are forty lakhs of handlooms including eight lakhs of domestic looms working in this country and with regard to the production capacity, he has stated only four thousand million metres of cloth. It is not correct. The handlooms are

capable of producing more than six-thousand million metres of cloth as per the indications given by the Textiles Commissioner. Further, the Minister says that there is no scarcity of yarn. When there is no short supply of yarn, why was there widespread unemployment among handloom weavers? Why have thousands of handloom weavers from Bihar migrated to eastern Delhi and working as coolie weavers? In Andhra Pradesh also, there was short supply.

Madam, this is the Report of the National Handloom Development Corporation. Here, they have stated:

> "With a difficult position in the availability of yarn, the Government have decided to import up to two lakh bales of duty-free cotton for spinning of yarn for exclusive use in the handloom sector besides many other steps taken—have put a brake in the rising trend. Though continued production of yarn is a matter of great concern."

Anyhow, they have stated that there was short supply of yarn and, therefore, the Government wanted to import two lakh bales of cotton, free of duty. That means they wanted to forego Rs. 10-crores to the mill owners by way of free import duty. That was not done. Madam, coming to the last point, the Minister said that 450 million kg of allowing import of cotton yarn was supplied to the mills. In the answer to Question (a), he says that the production capacity of the handlooms is only four thousand million metres. Four hundred million kg of yarn is sufficient to produce more than 4500 million metres of cloth. Therefore, there is a discrepancy between the answers given to Questions (a) and (b). At no time had the mills delivered 450 million kg of hank yarn. Even if they had delivered, one-third of the hank yarn was taken away by the powerlooms as agreed to by the Indian Cotton Mills Federation and also the Planning Commission... (Interruptions)... I am putting the question. I am coming to that. The availability of yarn is only 300 million kg of yarn and there are other users too—ball-thread makers, fishing nets and rope making there people also use hank yarn. There is no data with the Government as to how much of hank yarn was being utilised by the other users. In any case, the handlooms must have received less than 300 million kg of yarn which means forced unemployment for the handloom weavers for over six months in the year.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Will you please put the question, Mr. Kotaiah?

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Yes, I am putting my question. Is there any proposal with the Government to produce 225 million kgs. of yarn from the 109 co-operative spinning mills for the benefit of the weavers at stable and reasonable prices? If this done, definitely, the prices of hank yarn in the open market will come down.

श्री अशोक गहलोत : मैडम, कोटैया साहब के बारे में पूरा हाऊस जानता है कि इनका कमिटमेंट हैंडलूम वीवर्ज के साथ बना हुआ है । इनकी भावनाओं का हम हमेशा आदर करते हैं । जो समस्याएं इन्होंने समय-समय पर हमारे सामने रखी हैं, हम उनको हल करने की पूरी कोशिश भी करते हैं । जहां तक दो लाख बेल्स के इम्पोर्ट की बात मैं कह चुका हूं, वह अभी इम्पोर्ट नहीं हुई हैं । यह हमारी स्कीम इसलिए थी कि उनकी सप्लाई हम बढ़ा देंगे जिससे हैंडलूम वीवर्ज की शिकायतों में कमी आ सकेगी । कोटैया साहब ने स्वयं कहा है कि 38.9 लाख हथकरघे इस देश के अन्दर हैं । उसी को आधार बना कर के हम लोगों ने देखा है कि एवरेज 5.12 मीटर कपड़े का उत्पादन एक हथकरघे में होता है । इसका अगर हम हिसाब लगाते हैं तो वह जा कर 4152 मिलियन मीटर कपड़ा बैठता है। उसी के अनुसार यार्न की उपलब्धता की जो फिगर्ज हमारे पास हैं, उसके आधार पर हमने कहा

था कि 458 मिलियन किलोग्राम हैंक यार्न बुनकरों को मिलता है । इसके बावजूद मैं यह कहना चाहूंगा कि कोटैया साहब लास्ट टाइम भी शिकायत कर रहे थे, मैंने मंत्रालय को इस बात के लिए आदेश दिये हैं कि इसकी पुन: जांच करें और हैंक यार्न की यह जो फिगर्ज हैं इनका पूरे देशके अन्दर टेक्सटाइल कमिश्नर के माध्यम से सर्वे कराए और यह देखें कि वास्तव में जो मिल रहा है यह कितना मिल रहा है । मैं इतना ही कह सकता हू कि जो भी समस्याए हैंडलूम वीवर्ज के बारे में हैं, उनकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। जहां तक प्रागदा कोटैया साहब ने यह कहा कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बिहार से जो लोग आए हैं, वह बेरोजगार हो रहे हैं, मैडम, मैं यह कहना चाहूगा कि हैंडलूम वीवर्ज की अपनी स्वय की भी कई समस्याए हैं क्योंकि यह वीकेंड सेक्टर में फैला हुआ है, गांव और कस्बों में फैला हुआ है । लोग इसमें फुल टाइम काम नहीं करते हैं । कृषि में भी काम करते हैं, सप्लीमेंटरी काम के तौर पर इसमें काम करते हैं। इसके इलावा हैंडलूम के अन्दर लूम की क्वालिटी कैसी है, किस तरह के हैंडलूम बने हुए हैं, इन सब बातों पर भी निर्भर करता है । इसलिए यह कहना कि वह बेरोजगार होते जा रहे हैं, मैं समझता हू ऐसी बात नहीं है बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार समय मिलने पर हैंडलूम में काम करते हैं और दूसरे काम भी करते हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Shivajirao Giridhar Patil.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Madam as a matter of fact... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have asked your question. Some other Members also want to ask questions. They want to support you, Mr. Kotaiah. They want to support you. Yes, Mr. Patil.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: I am not going to ask many questions. I have one question only to ask. There are 109 spinning mills in the country in which the State Governments have invested capital to the extent of 51 per cent ... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is all right. Yes, Mr. Patil.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: I am putting my question, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not permitting. Mr. Patil... (*Interruptions*)...

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Madam, the State Governments have got 51 per cent of the capital in these mills. Will they utilize this to make available yarn to the handloom weavers?

SHRI AJIT P. K. JOGI: This was not replied, to Madam.

श्री अशोक गहलोत :इसको मैं एग्जामिन करवाऊंगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is going to get it examined and then give you the answer. Yes, Mr. Patil? You do not want to ask?... All right. Mr Ram Naresh Yadav.

श्री राम नरेश यादव : महोदया, यह बुनकरों की समस्या बहुत जटिल है । यह बात सही है कि जितने बुनकर इस देश में लगे हुए हैं, उनको जितना सूत चाहिये, वह नहीं मिल पा रहा है । यदि उनको सूत समय पर नहीं मिलता है तो उनके सामने कठिनाई उपस्थित हो जाती है। आपने यह कहा है कि 450 मिलियन किलोग्रोम हैंक यार्न हमारे लिए अवेलेबल है मैं यह जानना चाहता हू कि जब इतनी उपलब्धता है तो डिमांड कितनी है ? हमारे देश में कई लाख हैंडलूम लगे हुए हैं, मैं यह जानना चाहता हू हैंडलूम्स और पावरलूम्स की कितनी डिमांड है और उस डिमांड के आधार पर जब आपकी उपलब्धता कम है तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ताकि पूरे देश के बुनकरों के सामने भुखमरी की स्थिति न आने पाए ? इस आधार पर विचार करते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हू कि वे

क्या कदम उठाने जा रहे हैं ताकि उन बुनकरों के सामनें जो समस्याएं हैं, सूत की कमी है, सूत के दाम जो बढ़ेंगे उस समस्या का समाधान आप कैसे करने जा रहे हैं ?

श्री अशोक गहलोत : मैडम, मैं यह कह चुका हूं कि जो हमारे पास हथकरघे हैं ये करीब 39.9 लाख हैं जिसमें 22.1 लाख कर्माशियल हैं और 16.8 लाख डोमेस्टिक हैं । जो ऐवरेज़ पर लूम आता है प्रोडक्शन का, वह 5.12 मीटर्स है । हमने हिसाब लगाया है कि अगर 300 दिन भी काम करें तो जा करके 4,152 मिलियन मीटर्स कपड़ा बनता है । तो जितनी कैपेसिटी है उतना ही करीब करीब हैंक यार्न उपलब्ध होने के आंकड़े मेरे पास हैं । परन्तु जैसा मैंने अभी कहा है कि शिकायतें है कि नहीं, इतना हैंक यार्न नहीं मिलता है । मैं आपके मायध्म से माननीय सदस्य और सदन को कहना चाहूंगा कि इसमें वापस हम दुबारा पूरी तरह से छानबीन करेंगे कि ये जो आकड़े हैं और इसमें जो शिकायतें आ रही हैं, क्या इसमें कोई कमी है । . . . **(व्यवधान)** अभी तक हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनमें बराबर कोई कमी नजर नहीं आ रही है ।

श्री राम नरेश यादव : आंकड़े तो. महोदय सही नहीं हैं. . . **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Gurudas Das Gupta.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: It is not at all available to the handloom weavers...

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is not the way. Please.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: In view of the serious catastrophe in the field of textiles, including the handlooms, the NTC and production of raw cotton—we know your political commitment; the Congress Government is committed to produce janata cloth and low priced textiles for the common people of the country—in view of the serious develpments which the Minister's statement unfolds one after the other, there is widespread pauperisation of the handloom workers. The Government has to go is for import of raw cotton. The NTC mills are not producing enough. The reasons are known to him. We also know the reasons. Therefore, in view of all this, is the Government contemplating to give a fersh look to the textile policy, the entire textile policy.

श्री अशोक गहलोत : मैडम, माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाये थे वे पहले मेन सवाल में आ चुके। थे, मैं कह चुका हूं कि अभी दो लाख बेल की जो स्कीम थी उसको पूरा नहीं किया है । जहां तक जनता क्लोथ की बात है उसको हम लोगों ने अभी तक चालू कर रखा है। इन सब बातों को देखते हुए हमने एन.टी.सी. के रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्लान बनाया है उसको पूरा करने के बाद ही हम कह सकेंगे कि कितना हैंक यार्न कम बनने की जो शिकायत आ रही है उसको हम पूरा कर सकेंगे । जहां तक टेक्सटाइल पालिसी से इसको जोड़ने का सवाल है, मैं समझता हूं कि टेक्सलाइल पालिसी की बात अलग से है । उसको मै अलग से चाहूंगा कि क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसके ऊपर बात कर सकेंगे । उससे इसका लिंक नहीं है ।

उपसभापति : नहीं, वे कह रहे हैं कि इतनी सब गड़बड़ उन लोगों को दिख रही है . .

....What is saying is that there is a lot of unhappiness among the textile workers and the handloom workers, and they the NTC is not working up to its capacity. You yourself admited that it is working up to 20 per cent only. So, are you going to review the textile policy?

श्री अशोक गहलोत : मैं निवेदन कर रहा हूं कि एन.टी.सी. की रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: He means the entire textiles because Mr. Kotaiah's problem is about the handloom weavers.

श्री अशोक गहलोत : अभी दो तीन साल पहले आबिद हुसैन कमेटी जो बनी थी उसकी रिकमेंडेशस हमारे पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं । जब तक उस पर फैसला नहीं करते हैं तब तक नयी पालिसी लाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I seek your protection. (*Interruptions*)

SHRI PRAGADA KOTAIAH: The Minister has promised to place the Abid Hussain Committee report before the House ... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: There must be complaints from all sides of the House. There is a crisis in the textile industry... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order. Mr. Gurudas Das Gupta, I know what you are telling. I will explain.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Just a minute, Madam. There are complaints from all quarters that there is a serious problem in the textiles. The Minister does not admit that there is a problem. At the same time, the Minister does not say that there is a complaint there is a serious problem and that he will review it. He says that he is going to restructure the NTC. How long will he take? Workers are not getting the wages. 5 textile mills in Kanpur are just...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: How long will the Government take?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Gurudas Das Gupta, please take your seat.

श्री अशोक गहलोत : मैडम एन०टी०सी० के सवाल... (**व्यवधान**)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I said, please take your seat. That is what I said.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Let the Minister speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Minister said that he has got this Abid Hussain Committee report.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: There is no answer to my question.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 467.

Demand by advocates of M.P. for working in Hindi

*467. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that advocates in the State of Madhya Pradesh are agitating for working in Hindi language by the High Court and its benches in the State;

(b) if so, what remedial action Government have taken so far in this regard;

(c) whether Government propose to accept the demand of the advocates; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना